NITIN SIR CLASSES

THE HINDU

INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Thursday, 27 Nov, 2025

Edition : International

Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 2 : Indian Polity / Prelims	सीजेआई ने कहा, अदालत एनजेएसी को पुनर्जीवित करने, कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करेगी
Page 04 Syllabus : GS 2 : International Relations	जन-केंद्रित संबंधों को सुधारने में चीन की मनमानी कार्रवाई 'मददगार' : भारत
Page 07 Syllabus : GS 3 : Science and Tech / Prelims	वाईफाई सिग्नल चुपचाप आपकी निगरानी कर सकते हैं: अध्ययन
Page 08 Syllabus : GS 3 : Indian Economy / Prelims	भारत को रुपये को स्थिर करने के लिए तेल आयात पर निर्भरता कम करनी चाहिए
Page 09 Syllabus : GS 2 : International Relations	एक जटिल वैश्विक प्रतिमान को कैसे नेविगेट करें
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus : GS 3 : Environment	COP30 ने 'कार्यान्वयन' पर ध्यान केंद्रित करके कथा को बदलने की मांग की

Page 01 : GS 2 : Indian Polity / Prelims

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के पुनरुद्धार और कॉलेजियम प्रणाली को बंद करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर सकता है।

- यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 99वें संविधान संशोधन और एनजेएसी अधिनियम (2015) को रद्द करने के लगभग एक दशक बाद हुआ है, जो न्यायिक स्वतंत्रता के आधार पर कॉलेजियम प्रणाली को बहाल करता है, जो मूल संरचना का एक हिस्सा है। वर्तमान याचिका में 2015 के फैसले को "बहुत गलत" कहा गया है, जो संवैधानिक अदालतों में नियुक्तियों में शक्तियों के पृथक्करण, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर चर्चा को पुनर्जीवित करता है।

CJI says court will consider plea seeking to revive NJAC, end the Collegium system

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Chief Justice of India Surya Kant on Wednesday orally said the court would consider a plea seeking to revive the National Judicial Appointments Commission and bring an end to the Collegium system of judicial appointments to the constitutional courts.

The plea, which arraigns the Chief Justice of India and even the Supreme Court Collegium as respondents along with the Union government and a clutch of parties, submitted that the striking down of the NJAC by the court was a "great wrong because it meant substitution of the will of the people by the opinion of the four judges".

The oral mentioning of the application was made by advocate Mathews J. Nedumpara, who has sought permission to argue the case in-person.

The NJAC, which briefly gave the government an equal role along with the judiciary in the appointment of judges to constitutional courts, was struck down by the court in 2015 as unconstitutional.

The plea urged the 2015 judgment to be rendered *void ab initio* as it revived the Collegium system, which was a "synonym for nepotism and favouritism."

"Since the Collegium came into existence, appointments to higher judiciary have been a 'riddle wrapped in a mystery, inside an enigma' to borrow an expression from Winston Churchill... The Parliament, which represents the will of the people,had enacted the 99th Constitutional Amendment Act and the NJAC Act. However, the enactments were "quashed and set aside" by this court, reducing the Parliament to an inferior tribunal," it said.

History revisited

1993: Collegium system of judicial appointments **came into existence** by virtue of a Constitution Bench judgment

2014: The National Judicial Appointments Commission Act, 2014 and the Constitution (99th Amendment) Act, 2014 came into existence **to substitute** the Collegium system

2015: A Bench declared the 99th Constitutional Amendment Act and the NJAC Act unconstitutional, **reviving the Collegium system**

मुख्य विश्लेषण

1. पृष्ठभूमि: कॉलेजियम बनाम एनजेएसी

- कॉलेजियम प्रणाली: तीन न्यायाधीशों के मामलों के माध्यम से विकसित हुई, जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका को प्राथमिकता देती है।
- एनजेएसी (2014-2015): 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से पेश किया गया; नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका, कार्यपालिका और आम लोगों को शामिल किया गया।
- 2015 का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत, विशेष रूप से न्यायिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का हवाला देते हुए एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया।

2. वर्तमान याचिका क्या तर्क देती है

याचिका में मजबूत दावा किया गया है:

- 2015 के फैसले ने "लोगों की इच्छा को चार न्यायाधीशों की राय से बदल दिया।
- कॉलेजियम को "भाई-भतीजावाद और पक्षपात का पर्याय" बताया।
- तर्क देता है कि लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद को "अवर न्यायाधिकरण" में बदल दिया गया था।
- 2015 के फैसले को शुरू से ही शून्य घोषित करने की मांग की।
- कॉलेजियम के कामकाज में पारदर्शिता की कमी की ओर इशारा करते हैं - जिसे अक्सर "एक रहस्य में लिपटी पहेली" कहा जाता है ... एक पहेली के अंदर।

3. यह क्यों मायने रखता है: समकालीन महत्व

- नियुक्तियों में देरी और पारदर्शिता के संबंध में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बार-बार टकराव होता है।
- सांसदों और केंद्र सरकार ने बार-बार अपारदर्शिता के बारे में चिंता व्यक्त की है।
- अदालत ने हाल ही में कॉलेजियम की सिफारिशों के लिए प्रस्ताव और कारण जारी किए हैं, लेकिन आलोचनाएं बनी हुई हैं।
- पुनरुद्धार याचिका - हालांकि कानूनी रूप से जटिल - एक राजनीतिक और संवैधानिक रूप से संवेदनशील बहस को फिर से खोलती है।

4. इसमें शामिल संवैधानिक मुद्दे

a) न्यायिक स्वतंत्रता

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को समान अधिकार देने से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है।
- मूल संरचना का हिस्सा है (केशवानंद भारती, एस.पी. गुप्ता, द्वितीय न्यायाधीश मामले के अनुसार)।

b) शक्तियों का पृथक्करण

- 99वें संशोधन ने एक सहयोगी योजना का प्रयास किया; आलोचकों का कहना है कि इसने संतुलन को कार्यपालिका की ओर झुका दिया।

ग) संसदीय सर्वोच्चता बनाम संवैधानिक सर्वोच्चता

- याचिका में तर्क दिया गया है कि संसद के फैसले को केवल "न्यायिक राय" पर पलटा नहीं जा सकता है।
- हालांकि, संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा अच्छी तरह से स्थापित है (मिनर्वा मिल्स, आईआर कोएल्हो)।

5. अब न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न

- क्या नौ साल पुराने संविधान पीठ के फैसले को फिर से खोला जा सकता है?
- क्या नए संविधान संशोधन के बिना 99वें संशोधन और एनजेएसी अधिनियम को पुनर्जीवित किया जा सकता है?
- क्या कॉलेजियम प्रणाली संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, या केवल एक विकसित परंपरा है?

समाप्ति

[redacted]

सीजेआई का यह बयान कि अदालत एनजेएसी को पुनर्जीवित करने की याचिका पर विचार कर सकती है, भारत में न्यायिक नियुक्तियों पर चल रहे विमर्श में एक महत्वपूर्ण क्षण है। जबकि याचिका कॉलेजियम प्रणाली की वैधता और पारदर्शिता को चुनौती देती है, न्यायपालिका ने लगातार न्यायिक स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए अपनी प्रधानता को आवश्यक माना है, जो संविधान की मूल संरचना की आधारशिला है। क्या सुप्रीम कोर्ट 2015 के फैसले पर फिर से विचार करेगा, फिर से पुष्टि करेगा या फिर से व्याख्या करेगा, यह देखा जाना बाकी है, लेकिन यह मुद्दा भारत के लोकतंत्र में शक्तियों के संतुलन के लिए दूरगामी प्रभावों के साथ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस को फिर से खोलने के लिए तैयार है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसकी स्थापना 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से की गई थी।

2. एनजेएसी में न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज के सदस्य शामिल थे।

3. सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2

B. केवल 2

C. केवल 1 और 3

D. 1, 2 और 3

उत्तर : a)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: एनजेएसी को पुनर्जीवित करने की याचिकाओं पर विचार करने की सुप्रीम कोर्ट की इच्छा ने भारत में न्यायिक नियुक्तियों पर चर्चा को फिर से शुरू कर दिया है। इस बहस के संवैधानिक, संस्थागत और लोकतांत्रिक आयामों का विश्लेषण करें। **(150 शब्द)**

Page 04 : GS 2 : International Relations

भारत ने अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय नागरिक को शंघाई हवाई अड्डे पर चीन द्वारा 'मनमाने' ढंग से हिरासत में लिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे एक ऐसी कार्रवाई करार दिया है जो आपसी विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों को कमजोर करती है।

- विदेश मंत्रालय ने अपने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के माध्यम से इस बात पर जोर दिया कि भारत-चीन संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता पहली शर्त है। इस घटना ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावों के साथ-साथ 2020 के बाद द्विपक्षीय संबंधों की नाजुक प्रकृति के बारे में संवेदनशीलता को सामने ला दिया है।

Arbitrary actions by China 'unhelpful' in improving people-centric ties: India

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Days after Chinese officials detained an Indian citizen from Arunachal Pradesh at Shanghai international airport, Randhir Jaiswal, official spokesperson of the External Affairs Ministry, said, "arbitrary actions" by China are "most unhelpful" in nurturing "people-centric" initiatives.

Mr. Jaiswal further said that "peace and tranquillity" on the India-China border is the "prerequisite" for the development of ties.

Mr. Jaiswal's remarks came a day after the External Affairs Ministry said a "strong demarche" was sent to the Chinese side soon after the detention of Pema Wang Thongdok became known.

"Arbitrary actions by China as I referred to involving an Indian citizen from Arunachal Pradesh are most unhelpful towards efforts being made by both sides to build mutual trust and understanding and gradually move towards normalisation of bilateral relations," said Mr. Jaiswal.

Randhir Jaiswal

Mr. Jaiswal emphasised that Arunachal Pradesh is an "integral and inalienable part of India and this is a fact that is self evident. No amount of denial by the Chinese side will change this indisputable reality."

Ms. Thongdok had said that she was detained in Shanghai airport over claims "that my Indian passport was invalid as my birthplace is Arunachal Pradesh, which they claimed is Chinese territory."

"Maintenance of peace and tranquillity in the border regions is a prerequisite for the continued and overall development of India-China bilateral relations. Our position in this regard has always been very clear and consistent. Since October 2024, both sides have worked closely to maintain peace and tranquility in the border regions," Mr. Jaiswal said.

China Eastern Airlines started its Shanghai-Delhi service on November 9, 2025, after the Indian and Chinese leadership met on August 31, 2025 on the sidelines of the SCO summit in Tianjin.

मुख्य विश्लेषण

1. क्या हुआ?

- अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय नागरिक पेमा वांग थोंगडोक को शंघाई हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया।
- चीनी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि उनका भारतीय पासपोर्ट 'अमान्य' है क्योंकि उनका जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश 'चीनी क्षेत्र' है।
- भारत ने तुरंत चीन को एक कड़ा विरोध जारी कर उसकी रिहाई और स्पष्टीकरण की मांग की।

2. भारत की आधिकारिक स्थिति

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा:

- चीन की मनमानी कार्रवाई लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने में "सबसे असहायक" है।
- अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, और चीन द्वारा बार-बार किए जाने वाले कोई भी दावे इस तथ्य को बदल नहीं सकते हैं।
- अक्टूबर 2024 से, दोनों पक्ष सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं - जो संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक है।

यह भारत के निरंतर रुख को उजागर करता है कि सीमा स्थिरता चीन के साथ किसी भी राजनयिक या आर्थिक जुड़ाव के लिए आधारभूत है।

3. यह घटना क्यों मायने रखती है

a) अरुणाचल प्रदेश पर चीन का लगातार दावा

- चीन नियमित रूप से नत्थी वीजा जारी करता है, अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलता है और भारतीय नेताओं की यात्राओं का विरोध करता है।
- जन्मस्थान पर एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक भारतीय नागरिक को हिरासत में लेना प्रशासनिक दावों में वृद्धि का प्रतीक है।

b) गलवान के बाद नाजुक द्विपक्षीय संबंध (2020)

- कोर कमांडर वार्ता के कई दौर के बावजूद, प्रमुख क्षेत्रों में डिसइंगेजमेंट अधूरा है।
- भारत का कहना है कि शांतिपूर्ण सीमाओं के बिना सामान्यीकरण असंभव है, इस बयान में दोहराया गया है।

ग) विश्वास-निर्माण उपायों (सीबीएम) को कमजोर करना

- भारत और चीन ने तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन (अगस्त 2025) में नेताओं की बैठक के बाद नवंबर 2025 में ही उड़ानें (शंघाई-दिल्ली मार्ग) फिर से शुरू कीं।
- ऐसी घटनाओं से विश्वास, व्यापार और यात्रा के नाजुक पुनर्निर्माण का खतरा है।

4. व्यापक भू-राजनीतिक प्रासंगिकता

- यह चीन के "मानक मानचित्र कूटनीति" के तहत मुखर रुख को दर्शाता है।

- राजनयिक संदेश के माध्यम से चीन के आक्रामक रुख का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के भारत के प्रयास को पुष्ट करता है।
- जन-केंद्रित पहलों को प्रभावित करता है जैसे:
    - पर्यटन-व्यवसाय
    - शैक्षणिक आदान-प्रदान
    - व्यापार गतिशीलता
    - सांस्कृतिक संपर्क

ये दीर्घकालिक संबंधों को स्थिर करने के लिए आवश्यक हैं।

समाप्ति

अरुणाचल प्रदेश के एक नागरिक को चीन द्वारा हिरासत में लिए जाने पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया संप्रभुता के दावों और भारत-चीन संबंधों के अनिश्चित प्रक्षेपवक्र को लेकर जारी तनाव को रेखांकित करती है। यह दोहराते हुए कि सीमा पर शांति और स्थिरता द्विपक्षीय सामान्यीकरण के लिए गैर-परक्राम्य पूर्वापेक्षाएं हैं, भारत संकेत देता है कि एकतरफा या मनमाने चीनी कार्रवाइयां विश्वास निर्माण में बाधा उत्पन्न करेंगी। आगे बढ़ते हुए, दोनों देशों को एक स्थिर और पूर्वानुमानित संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए संवाद, समझौतों के पालन और एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर भरोसा करना चाहिए।

UPSC Mains Practice Question

अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बार-बार प्रशासनिक और राजनयिक दावों का द्विपक्षीय विश्वास और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है। चर्चा करना। **(150 शब्द)**

□□□□□ □□□□□□

Page : 07 : GS 3 : Science and Tech / Prelims

जर्मनी के कार्लज़ूए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि साधारण वाईफाई सिग्नल - विशेष रूप से बीमफॉर्मिंग फीडबैक इंफॉर्मेशन (बीएफआई) - का उपयोग वाईफाई नेटवर्क तक पहुंचने के बिना भी अत्यधिक उच्च सटीकता वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। यह निष्कर्ष डिजिटल गोपनीयता, रोजमर्रा की प्रौद्योगिकियों और गुप्त निगरानी के चौराहे पर एक उभरते खतरे को उजागर करता है, जो नीति-निर्माण, साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करता है।

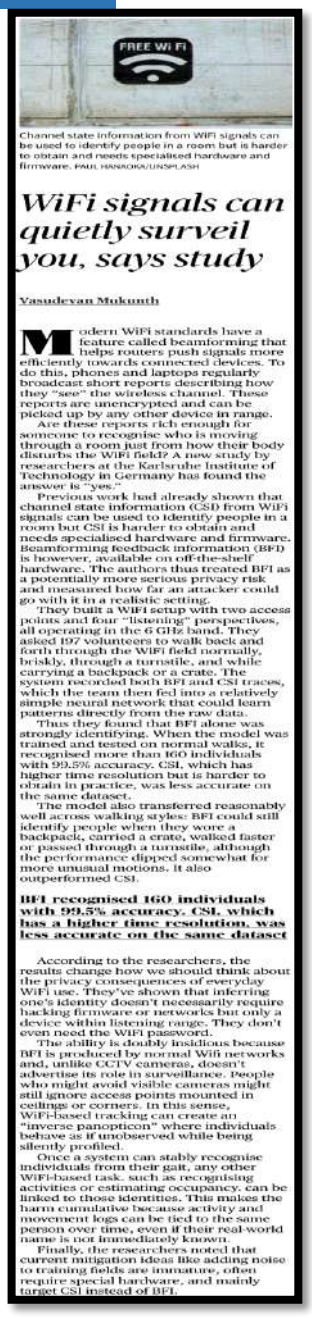

मुख्य विश्लेषण

1. वाईफाई लोगों की पहचान कैसे कर सकता है

- आधुनिक वाईफाई बीमफॉर्मिंग का उपयोग करता है, जिसके लिए कनेक्टेड उपकरणों को समय-समय पर बीएफआई रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता होती है जिसमें बताया गया है कि वे वायरलेस चैनल को कैसे देखते हैं।
- ये बीएफआई पैकेट अनएन्क्रिप्टेड, सार्वजनिक रूप से प्रसारित होते हैं, और पासवर्ड के बिना भी सीमा के भीतर किसी भी डिवाइस द्वारा इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं।
- अध्ययन से पता चलता है कि ये बीएफआई सिग्नल व्यक्तियों को उनकी चाल से पहचानने के लिए पर्याप्त जानकारी रखते हैं।

2. अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- शोधकर्ताओं ने 6 गीगाहर्ट्ज वाईफाई बैंड का उपयोग करके दो एक्सेस पॉइंट और चार लिसनिंग पॉइंट्स के साथ एक सेटअप बनाया।
- 197 स्वयंसेवकों ने विभिन्न चलने के कार्य किए - सामान्य, तेज, टर्नस्टाइल, बैकपैक या टोकरा ले जाना।
- कच्चे सिग्नल डेटा पर प्रशिक्षित एक तंत्रिका नेटवर्क ने दिखाया:
  - अकेले बीएफआई का उपयोग करने वाले 160 से अधिक व्यक्तियों की पहचान करने में 99.5% सटीकता।
  - बीएफआई ने सीएसआई को पीछे छोड़ दिया, जिसे पहले मुख्य खतरा माना जाता था, लेकिन इसके लिए विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता होती है।
  - विभिन्न चलने की शैलियों में पहचान प्रभावी रही, हालांकि असामान्य आंदोलनों के दौरान थोड़ी सटीकता में गिरावट आई।

3. यह एक गंभीर गोपनीयता चिंता क्यों है

a) कोई हैकिंग की आवश्यकता नहीं है

- हमलावर को केवल सुनने की सीमा के भीतर एक उपकरण की आवश्यकता होती है।
- वाईफाई पासवर्ड या फर्मवेयर तक पहुंच की आवश्यकता नहीं है।

बी) अदृश्य निगरानी ("उलटा पैनोप्टिकॉन")

- सीसीटीवी कैमरों के विपरीत, वाईफाई एक्सेस पॉइंट उनकी निगरानी क्षमता को प्रकट नहीं करते हैं।
- व्यक्ति ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि चुपचाप प्रोफाइल किए जाने के दौरान अनदेखा किया जा रहा हो।

ग) संचयी नुकसान

Channel state information from WiFi signals can be used to identify people in a room but is harder to obtain and needs specialised hardware and firmware. PAUL HANAOKA/UNSPLASH

WiFi signals can quietly surveil you, says study

Vasudevan Mukunth

Modern WiFi standards have a feature called beamforming that helps routers push signals more efficiently towards connected devices. To do this, phones and laptops regularly broadcast short reports describing how they "see" the wireless channel. These reports are unencrypted and can be picked up by any other device in range.

Are these reports rich enough for someone to recognise who is moving through a room just from how their body disturbs the WiFi field? A new study by researchers at the Karlsruhe Institute of Technology in Germany has found the answer is "yes."

Previous work had already shown that channel state information (CSI) from WiFi signals can be used to identify people in a room but CSI is harder to obtain and needs specialised hardware and firmware. Beamforming feedback information (BFI) is however, available on off-the-shelf hardware. The authors thus treated BFI as a potentially more serious privacy risk and measured how far an attacker could go with it in a realistic setting.

They built a WiFi setup with two access points and four "listening" perspectives, all operating in the 6 GHz band. They asked 197 volunteers to walk back and forth through the WiFi field normally, briskly, through a turnstile, and while carrying a backpack or a crate. The system recorded both BFI and CSI traces, which the team then fed into a relatively simple neural network that could learn patterns directly from the raw data.

Thus they found that BFI alone was strongly identifying. When the model was trained and tested on normal walks, it recognised more than 160 individuals with 99.5% accuracy. CSI, which has higher time resolution but is harder to obtain in practice, was less accurate on the same dataset.

The model also transferred reasonably well across walking styles: BFI could still identify people when they wore a backpack, carried a crate, walked faster or passed through a turnstile, although the performance dipped somewhat for more unusual motions. It also outperformed CSI.

BFI recognised 160 individuals with 99.5% accuracy. CSI, which has a higher time resolution, was less accurate on the same dataset

According to the researchers, the results change how we should think about the privacy consequences of everyday WiFi use. They've shown that inferring one's identity doesn't necessarily require hacking firmware or networks but only a device within listening range. They don't even need the WiFi password.

The ability is doubly insidious because BFI is produced by normal Wifi networks and, unlike CCTV cameras, doesn't advertise its role in surveillance. People who might avoid visible cameras might still ignore access points mounted in ceilings or corners. In this sense, WiFi-based tracking can create an "inverse panopticon" where individuals behave as if unobserved while being silently profiled.

Once a system can stably recognise individuals from their gait, any other WiFi-based task, such as recognising activities or estimating occupancy, can be linked to those identities. This makes the harm cumulative because activity and movement logs can be tied to the same person over time, even if their real-world name is not immediately known.

Finally, the researchers noted that current mitigation ideas like adding noise to training fields are immature, often require special hardware, and mainly target CSI instead of BFI.

- एक बार चाल से पहचान का अनुमान लगाया जाता है:
    - गतिविधि पैटर्न
    - अधिभोग स्तर
    - दैनिक आंदोलनों को समय के साथ एक ही व्यक्ति से जोड़ा जा सकता है, विस्तृत व्यवहार प्रोफाइल बनाया जा सकता है।

घ) निगरानी उपकरण के रूप में रोजमर्रा का बुनियादी ढांचा

- वाईफाई राउटर हर जगह मौजूद हैं - घरों, कार्यालयों, मॉल, हवाई अड्डों - संभावित दुरुपयोग को व्यापक बनाते हैं।

4. भारत के लिए निहितार्थ

a) निजता का अधिकार (पुट्टास्वामी जजमेंट, 2017)

- दिखाता है कि कैसे गैर-व्यक्तिगत, परिवेश संकेत अभी भी व्यक्तिगत पहचान प्रकट कर सकते हैं।
- पारंपरिक व्यक्तिगत डेटा से परे मजबूत डेटा सुरक्षा ढांचे की आवश्यकता को मजबूत करता है।

b) भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA), 2023 में अंतराल

- डीपीडीपीए स्वेच्छा से प्रदान किए गए व्यक्तिगत डेटा पर ध्यान केंद्रित करता है।
- पूरी तरह से गैर-सहमति वाले शारीरिक हस्ताक्षरों को कवर नहीं करता है, जैसे कि वाईफाई सिग्नल से निकाले गए चाल पैटर्न।

c) राष्ट्रीय सुरक्षा और काउंटर-सर्विलांस

- गुप्त ट्रैकिंग का शोषण किया जा सकता है:
    - शत्रुतापूर्ण अभिनेता
    - कॉर्पोरेट निगरानी
    - राज्य की अधिकता
    - प्रतिबंधित क्षेत्रों में व्यक्तियों को लक्षित करने वाले अपराधी

d) अद्यतन साइबर मानदंडों की आवश्यकता

- नियामकों को अनिवार्य करने की आवश्यकता हो सकती है:
    - बीमफॉर्मिंग मेटाडेटा का एन्क्रिप्शन
    - गोपनीयता-दर-डिज़ाइन प्रोटोकॉल
    - राउटर और एक्सेस पॉइंट के लिए मानक

5. सीमाएँ और शमन चुनौतियाँ

- शोधकर्ताओं ने मौजूदा शमन विधियों (जैसे, शोर जोड़ना) का उल्लेख किया:
    - पिछड़ा
    - हार्डवेयर पर निर्भर
    - ज्यादातर सीएसआई के उद्देश्य से, बीएफआई के लिए नहीं
- सुझाव देता है कि दुनिया निगरानी के इस रूप के लिए तैयार नहीं है।

□□□□□ □□□□□□

समाप्ति

अध्ययन इस बात को रेखांकित करता है कि कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन की गई वाईफाई जैसी रोजमर्रा की प्रौद्योगिकियां अनजाने में गुप्त बायोमेट्रिक निगरानी के लिए परिष्कृत उपकरण बन सकती हैं। अनएन्क्रिप्टेड बीएफआई सिग्नल से व्यक्तियों की पहचान करने की क्षमता गोपनीयता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है और साइबर सुरक्षा मानदंडों, डेटा सुरक्षा कानून और अंतरराष्ट्रीय मानकों में तत्काल अपडेट की मांग करती है। भारत जैसे देशों के लिए, निष्कर्ष डिजिटल अधिकारों की बहस के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि तकनीकी प्रगति नागरिक स्वायत्तता और संवैधानिक गोपनीयता सुरक्षा से समझौता नहीं करती है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: आधुनिक वाईफाई सिस्टम में देखी जाने वाली बीमफॉर्मिंग फीडबैक सूचना (बीएफआई) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बीएफआई पैकेट एन्क्रिप्टेड हैं और वाईफाई पासवर्ड के बिना एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं।

2. बीएफआई मानव चाल पैटर्न को प्रकट कर सकता है जिसका उपयोग व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।

3. बीएफआई वाईफाई नेटवर्क के सामान्य कामकाज के हिस्से के रूप में उत्पन्न होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. 1 और 2

B. 2 और 3

C. 1 और 3

D. केवल 3

उत्तर: b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : क्या नैतिक चिंताएं उत्पन्न होती हैं जब वाईफाई राउटर जैसी परिवेशी प्रौद्योगिकियां चुपचाप व्यक्तियों को प्रोफाइल कर सकती हैं? सहमति, स्वायत्तता और "उलटा पैनोप्टिकॉन" की अवधारणाओं के संदर्भ में चर्चा करें। **(250 शब्द)**

□□□□□ □□□□□□□

Page 08 : GS 3 : Indian Economy / Prelims

भारतीय रुपये में तेजी से गिरावट आई है — नवंबर 2024 के अंत से नवंबर 2025 के बीच लगभग 7%, ₹83.4/$ से लगभग ₹89.2/$ तक स्लाइड कर रहा है. हालांकि रुपये में उतार-चढ़ाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन वर्तमान मूल्यह्रास गहरी संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर करता है, विशेष रूप से कच्चे तेल के आयात पर भारत की भारी निर्भरता, जो कुल आयात का 20% से अधिक है। वैश्विक डॉलर की मजबूती, बढ़ते चालू खाता घाटे (सीएडी) और महंगे तेल संक्रमण की पृष्ठभूमि में, संपादकीय में तर्क दिया गया है कि रुपये को स्थिर करने के लिए मौद्रिक उपकरणों से परे दीर्घकालिक सुधारों की आवश्यकता होती है – विशेष रूप से आयातित जीवाश्म ईंधन से दूर एक निर्णायक बदलाव।

□□□□□ □□□□□□□

Limited room

India must reduce dependence on oil imports to stabilise the rupee

Between late November 2024 and now, the rupee has depreciated about 7%, sliding from roughly ₹83.4 a dollar to about ₹89.2. This is not unprecedented as in 2018, it slid 11%-12% against the dollar. The comparison is instructive because the political and trade backdrops have echoes of that earlier period. In 2018, during the first term of U.S. President Donald Trump, global dollar strength, rising U.S. interest rates and trade tensions pressured emerging market currencies, including the rupee. The RBI used its first longer-term currency-swap as a systemic liquidity check. In 2019, it completed a $5 billion three-year dollar/rupee swap. And in February 2025, it carried out a $10 billion dollar/rupee buy-sell swap auction to infuse long-term rupee liquidity into the banking system under global stress. Such swaps are a standard tool by central banks to supply liquidity, shore up forex reserves and prevent disorderly currency depreciation when the dollar surges or capital flows reverse. The steep rupee slide in November arises in a context of external pressures – a widening current-account deficit, driven partly by higher imports of bullion, as a hedge in uncertain times, and exporters scrambling to maintain competitiveness amid high U.S. trade tariffs. In such a hostile global macro-environment, the RBI's mandate is limited: under the floating-but-managed regime, it can only 'smoothen volatility' rather than fix the exchange rate.

Between November last year and now, the RBI sold a net of roughly $50 billion in forex to stabilise the rupee. Even so, the slide has proceeded, highlighting the external pressures. That said, there is room for cautious optimism. India's foreign exchange reserves are comfortable – close to $693 billion. On the domestic front, retail inflation has slumped: headline CPI inflation came in at just 0.25% in October 2025, well below the RBI's target-band of 2%-6%. This gives the RBI space to tolerate modest currency depreciation without triggering aggressive rate hikes especially as India transitions from cheaper Russian crude to relatively costlier U.S. oil imports. With crude accounting for over a fifth of total imports in FY25, rupee depreciation combined with costlier oil imports could exert upward pressure on inflation. Given this environment, monetary stabilisation alone cannot suffice. The Centre must address India's long-standing vulnerability: heavy dependence on oil. Steps such as faster transport electrification must be treated as strategic imperatives and pursued with urgency. These must be done with a well thought-out trade policy, as opposed to a raft of bilateral trade deals that India has focused on , in the hope that these would diversify trade routes. If anything, trade agreements with Japan, the UAE and ASEAN have tilted the trade balance against India.

मुख्य विश्लेषण

1. संदर्भ: रुपया दबाव में क्यों है

कई वैश्विक और घरेलू कारक पहले के एपिसोड को प्रतिबिंबित करते हैं जैसे कि 2018 का मूल्यह्रास:

- वैश्विक डॉलर की मजबूती और अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने उभरते बाजार की मुद्राओं पर दबाव डाला है।
- उच्च अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय निर्यातकों को प्रभावित किया है, जिससे उन्हें कीमतों में कटौती करने के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे व्यापार संतुलन बिगड़ गया है।
- CAD को चौड़ा करना, द्वारा संचालित:
    - अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों में बचाव के रूप में बुलियन आयात में वृद्धि।
    - कच्चे तेल का आयात बिल ज्यादा है, खासकर जब भारत रियायती रूसी तेल से महंगे अमेरिकी तेल की ओर रुख करता है।

ये कारक भारत के बाहरी लचीलेपन को कम करते हैं, जिससे रुपया वैश्विक झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है।

2. प्रबंधित-फ्लोट व्यवस्था के तहत आरबीआई की सीमित भूमिका

- भारत एक फ्लोटिंग-लेकिन-प्रबंधित विनिमय दर का पालन करता है, जहां आरबीआई की भूमिका अस्थिरता को सुचारू करना है, न कि दर तय करना।
- बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप:
    - 2024 के अंत से 2025 के बीच, RBI ने रुपये को स्थिर करने के लिए लगभग $50 बिलियन बेचे.
    - फरवरी 2025 में, RBI ने दीर्घकालिक रुपये की तरलता को प्रभावित करने के लिए $10 बिलियन डॉलर/रुपये की खरीद-बिक्री स्वैप किया.
- इन कार्रवाइयों के बावजूद, रुपया लगातार कमजोर होता रहा – यह दर्शाता है कि अकेले मौद्रिक उपकरण संरचनात्मक कमजोरियों की भरपाई नहीं कर सकते हैं।

3. तेल निर्भरता रुपये को अस्थिर क्यों बनाती है

भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 85% आयात करता है। प्रभाव:

एक. तेल की ऊंची कीमतें → बड़ा आयात बिल → व्यापक चालू खाते की घाटे → रुपये का अवमूल्यन

दो. रुपये में गिरावट → महंगा तेल आयात → आयातित मुद्रास्फीति

तीन. वैश्विक बदलाव (उदाहरण के लिए, रूस छूट समाप्त हो रही है) → उच्च ऊर्जा लागत

यह एक आत्म-सुदृढ़ीकरण चक्र बनाता है जहां तेल निर्भरता बार-बार व्यापक आर्थिक स्थिरता को अस्थिर करती है।

हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति नाटकीय रूप से गिर गई है (अक्टूबर 2025 सीपीआई = 0.25%), महंगे तेल के साथ रुपये का अवमूल्यन भविष्य की मुद्रास्फीति को खतरे में डालता है।

4. संपादकीय में संरचनात्मक सुधारों की मांग क्यों की गई है

मुख्य संदेश: भारत को बाहरी भेद्यता को कम करने के लिए तेल निर्भरता में कटौती करनी चाहिए।

क) परिवहन का तेजी से विद्युतीकरण

- परिवहन पेट्रोलियम का एक बड़ा हिस्सा खपत करता है।
- ईवी, इलेक्ट्रिक बसों, माल ढुलाई के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और रेल विद्युतीकरण को तेजी से अपनाने से तेल आयात बिल कम हो जाता है।

b) मजबूत ऊर्जा सुरक्षा रणनीति

- ऊर्जा स्रोतों (सौर, पवन, परमाणु, जैव ईंधन) में विविधता लाने से तेल की कीमतों में आने वाले झटके का खतरा कम हो जाता है।
- रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार किया जाना चाहिए।

ग) व्यापार रणनीति पर पुनर्विचार

- भारत ने हाल ही में द्विपक्षीय एफटीए (जापान, यूएई, आसियान) पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे व्यापार मार्गों में विविधता आने की उम्मीद है।
- लेकिन इनमें से कई समझौतों ने भारत के खिलाफ व्यापार संतुलन को झुका दिया है।
- निर्यात का समर्थन करने और आयात-भारी क्षेत्रों के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए एक अधिक सुसंगत औद्योगिक + व्यापार नीति आवश्यक है।

5. अकेले मौद्रिक स्थिरीकरण क्यों काम नहीं करेगा

साथ भी:

- 693 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार
- बहुत कम मुद्रास्फीति, जिससे आरबीआई को मूल्यह्रास को सहन करने की अनुमति मिलती है

संरचनात्मक चुनौती बनी हुई है: जब तक भारत आयातित तेल पर बहुत अधिक निर्भर करता है, तब तक रुपया वैश्विक ऊर्जा की कीमतों और डॉलर की मजबूती के प्रति संवेदनशील बना रहेगा।

समाप्ति

2024-25 में रुपये का तेज अवमूल्यन गहरी संरचनात्मक कमजोरियों के सामने मौद्रिक हस्तक्षेपों की सीमाओं को दर्शाता है - उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आयातित कच्चे तेल पर भारत की अत्यधिक निर्भरता है। स्थायी मुद्रा स्थिरता के लिए, भारत को ऊर्जा विविधीकरण, परिवहन विद्युतीकरण और सुसंगत व्यापार नीति को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के रूप में मानना चाहिए। तेल निर्भरता को कम करना केवल एक पर्यावरणीय या आर्थिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि भारत के बाहरी क्षेत्र को मजबूत करने, रुपये को स्थिर करने और दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित कारकों पर विचार करें:

1. वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें

2. उच्च अमेरिकी ब्याज दरें

3. चालू खाता घाटा बढ़ाना

4. घरेलू मुद्रास्फीति में वृद्धि

उपरोक्त में से कितने सीधे भारतीय रुपये के मूल्यह्रास का कारण बन सकते हैं?

एक। केवल दो

जन्म। केवल तीन

C. सभी चार

D. केवल एक

उत्तर : c)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न : "कच्चे तेल के आयात पर भारत की उच्च निर्भरता रुपये की अस्थिरता का एक मूलभूत स्रोत है। चर्चा करना। **(150 शब्द)**

Page 10 : GS 2 : International Relations

अमेरिका-चीन संबंध आज वैश्विक भू-राजनीति के माहौल को परिभाषित करता है - जो अविश्वास, रणनीतिक चिंता और तकनीकी प्रतिद्वंद्विता से चिह्नित है। फिर भी दोनों देश गहराई से अन्योन्याश्रित बने हुए हैं। इस तनावपूर्ण परिदृश्य में, हांगकांग एक प्रतीकात्मक और व्यावहारिक "मध्य स्थान" के रूप में उभरता है, जहां राजनीतिक स्थिति के सख्त होने के बावजूद संवाद अभी भी संभव है। छठे चीन-यूनाइटेड स्टेट्स एक्सचेंज फाउंडेशन (CUSEF) फोरम (2025) ने आज की खंडित वैश्विक व्यवस्था को नेविगेट करने के लिए आवश्यक उपकरणों पर पुनर्विचार करने के लिए हांगकांग को एक सुविधाजनक बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया। भारत के लिए, ये चर्चाएं एक जटिल, बहुध्रुवीय दुनिया में रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती हैं।

How to navigate a complex global paradigm

In the tense relationship between the United States and China, Hong Kong emerges as a middle space — a vantage point from which to imagine a way forward. The city's unique position offers a metaphorical middle ground for dialogue, emphasising the need for new frameworks to navigate today's complex rivalries

A city of multitudes: The Hong Kong skyline in 2018. REUTERS

WORLD INSIGHT

Nirupama Rao

On November 17 and 18, 2025, Hong Kong hosted the sixth meeting of the China-United States Exchange Foundation (CUSEF), titled 'Circles for Peace'. Even though the U.S. and China remain locked in a tense, mistrustful relationship, they are also tied together more tightly than either side likes to admit. Here, Hong Kong, which has always lived between worlds, offers an uneasy middle space: a vantage point from which to imagine a way forward.

Complex rivalries

The discussions at the sixth U.S.-China Hong Kong Forum showed that trust had thinned, and that both the U.S. and China now operate as if expecting sudden shocks. Participants spoke with candour, and with a sense of fatigue. Old frameworks such as engagement, "guardrails", and managed competition no longer felt adequate for today's complex rivalry.

A persistent theme was the shrinking room for nuance. Strategic anxieties that once belonged to specialists have entered the public sphere, shaping domestic politics and narrowing the range of acceptable positions. It has also seeped into the human dimension of the relationship. American student numbers in China are far below pre-COVID-19 pandemic levels, and Chinese student enrolments in the U.S., once well above three lakh, have also declined. The deeper loss is familiarity — younger generations are encountering each other through narratives shaped by fear rather than through lived experience. Even though Presidents of both the nations anchor the relationship, personality-driven diplomacy is not enough in today's world.

Further, technology, and Artificial Intelligence (AI) were the biggest topics of conversations. It was observed that AI now resembles an international public good — too consequential to be monopolised or monetised by any single country. A credible governance regime, participants said, must rest on equity, transparency and accountability. This, however, brought up broader concerns about the overlap between civilian innovation and defence applications, especially in parts of the private sector. There would be an eventual need for an international governance mechanism for AI, and possibly for space ("the galaxy") as well. For if competition moves beyond the earth, who determines the rules?

The wider diplomatic climate also featured in the discussions, with the Taiwan question being a key issue. China argued that the discussion had become overwhelmingly militarised, and warned that American policy appeared to be drifting towards what Beijing views as a "one China, one Taiwan" (a position which advocates for the independence of Taiwan) posture. New mechanisms and a new vocabulary are needed to deal with the issue before it hardens into confrontation by default. One question discussed was whether the U.S. and China are prepared for another EP-3 incident (in 2001) — an accidental collision at sea or in the air that could escalate before political systems can respond. The region needs a crisis-prevention mechanism insulated from political swings.

Singapore's former Defence Minister Ng Eng Hen offered the broadest frame. He described this period as a "dialectic moment", where competing pressures reshape the global order but outcomes remain uncertain. The U.S., Europe and China will inevitably influence the emerging structure, he said, but the rest of the world should not allow the global commons to become collateral damage in major-power rivalry. The world does not need another hegemon, it needs powers capable of co-organising the future.

Hong Kong's future depends on preserving its cosmopolitan function — its connectivity, and cultural hybridity that allow ideas to cross borders even when politics cannot

Hong Kong's role

Throughout the forum, Hong Kong was in focus. While the city's limited geography stands out as a metaphor for the wider planetary condition, it is also becoming more China-centric, even as it tries to remain globally fluent. Its future depends on preserving its cosmopolitan function — its transparency, connectivity, and cultural hybridity that allow ideas to cross borders even when politics cannot. Hong Kong reminds one that the world's middle spaces still matter, revealing pathways that pure geopolitics often miss.

People-to-people ties emerged as a gentle theme of hope in the meeting. Participants noted that official relations may be strained, but human contact remains the ballast that prevents larger relationships from capsizing.

Hong Kong, despite the pressures of recent years, continues to make such exchanges possible.

Lessons for India

The conversations in the forum were a reminder that great-power relations may determine the climate of the world, but the weather is shaped by everyone else. India cannot control the forces buffeting the U.S.-China relationship, but can decide how to navigate them, and how to ensure that its own future is not written by default. Rigid binaries are unsustainable. India's task is not to imitate U.S. rhetoric nor to accept Chinese narratives at face value. It is to build domestic strength — technological, economic and institutional — to navigate a fractured world without losing strategic autonomy. The forum's emphasis on youth, cultural ties and the social contract around technology offered reminders that relationships are not made or unmade by summits alone. They are shaped by steady habits of engagement.

The shape of a new order

The clearest insight from the forum was that the U.S.-China relationship will not be restored to its old shape. The political atmospherics will remain turbulent. But the alternative to managed rivalry is not victory; it is a world of cascading risks — climate stress, pandemics, fragile supply chains, and polarised societies.

One participant put it simply that this was "A story we have to write together". The phrasing carries weight. It shifts the conversation from competition to stewardship, from ideology to survival. The next order, if it emerges at all, will depend less on grand bargains and more on practical cooperation on energy, health, finance, and AI governance.

As the forum ended and one stepped out into the evening, the view from the conference venue stayed, of a South China Sea almost motionless, and meditative, in quiet contrast to the anxieties that shape the region — a reminder of how places, like people, survive by embracing complexity and allowing themselves room to rethink. The U.S. and China will continue to compete, sometimes fiercely. The future needs steady hands to shape it.

India has its own long arc with China, marked by caution and conviction. Yet, in this moment of global uncertainty, the challenge for all three countries is the same: to choose responsibility over reflex, and to widen the narrow spaces where dialogue is still possible.

Hong Kong, in its imperfect, resilient way, showed that those spaces still exist.

Nirupama Rao is Foreign Secretary (retired) and Founder-Trustee, The South Asia Symphony Foundation

THE GIST

The discussions at the sixth U.S.-China Hong Kong Forum showed that trust had thinned, and that both the U.S. and China now operate as if expecting sudden shocks.

Hong Kong reminds one that the world's middle spaces still matter, revealing pathways that pure geopolitics often miss.

The clearest insight from the forum was that the U.S.-China relationship will not be restored to its old shape. The political atmospherics will remain turbulent.

मुख्य विश्लेषण

1. जटिल प्रतिद्वंद्विता का एक नया युग

हांगकांग फोरम ने अमेरिका-चीन की गतिशीलता में मूलभूत बदलावों का खुलासा किया:

- पुराने ढांचे-जुड़ाव, रेलिंग, प्रबंधित प्रतिस्पर्धा-अब पर्याप्त नहीं है।
- दोनों शक्तियां ऐसे काम करती हैं जैसे कि सैन्य, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में अचानक झटके लगने की आशंका है।

- विश्वास की कमी गहराती जा रही है।
- दोनों देशों में घरेलू राजनीति ने बारीकियों या समझौते के लिए जगह को कम कर दिया है।

यह सार्वजनिक धारणाओं में फैल गया है, लोगों से लोगों के बीच संबंध कम हो गए हैं और अकादमिक आदान-प्रदान को कम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां एक-दूसरे को जीवित अनुभव के बजाय भय के आख्यानों के माध्यम से जान सकती हैं।

2. प्रौद्योगिकी और एआई: नई फ्रंटलाइन

मंच की चर्चाओं में एआई हावी रहा:

- एआई अब एक अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक भलाई जैसा दिखता है - एक राज्य द्वारा नियंत्रित होने के लिए बहुत परिणामी।
- शासन को समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर निर्भर करना चाहिए।
- एआई में नागरिक-सैन्य ओवरलैप के बारे में चिंताएं बढ़ती हैं, खासकर निजी तकनीकी क्षेत्र में।
- प्रतिभागियों ने निम्नलिखित की आवश्यकता पर प्रकाश डाला:
    - वैश्विक एआई शासन तंत्र
    - अंतरिक्ष और उपग्रह प्रतियोगिता के लिए नियम

केंद्रीय डर: समझौतों के बिना, प्रतिस्पर्धा सीमाओं, महासागरों को पार कर सकती है, और अंततः इसे नियंत्रित करने के लिए किसी भी नियम के बिना अंतरिक्ष ("आकाशगंगा") में प्रवेश कर सकती है।

3. ताइवान, संकट और दुर्घटनाओं का जोखिम

- ताइवान का मुद्दा एक फ्लैशपॉइंट बना हुआ है। चीन को चिंता है कि अमेरिकी नीति "एक चीन, एक ताइवान" रुख की ओर बढ़ रही है।
- फोरम के प्रतिभागियों ने 2001 ईपी -3 टक्कर जैसे पिछले संकटों पर फिर से विचार किया, चेतावनी दी कि एक और दुर्घटना - समुद्र में या हवा में - राजनीतिक प्रणालियों की तुलना में तेजी से बढ़ सकती है।
- राजनीतिक उतार-चढ़ाव से अछूता एक संकट-रोकथाम तंत्र की तत्काल आवश्यकता है।

4. विश्व व्यवस्था में एक "द्वंद्वात्मक क्षण"

सिंगापुर के पूर्व रक्षा मंत्री एनजी इंग हेन ने इस क्षण को द्वंद्वात्मक के रूप में चित्रित किया - जहां प्रतिस्पर्धी दबाव वैश्विक व्यवस्था को नया आकार देते हैं, लेकिन परिणाम अनिश्चित रहते हैं।

चाबी छीन लेना:

- किसी भी राष्ट्र (यहां तक कि अमेरिका या चीन को भी नहीं) अगले आधिपत्य की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए।
- दुनिया को भविष्य के सह-आयोजकों की जरूरत है, न कि प्रमुख शक्तियों की।
- हांगकांग जैसे मध्य स्थान दिखाते हैं कि कैसे महाद्वीपीय, जुड़े हुए और पारदर्शी मंच प्रतिद्वंद्विता के बीच भी संवाद की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

5. हांगकांग की भूमिका: ध्रुवीकृत दुनिया में एक सीमांत स्थान

चीन-केंद्रित झुकाव के बावजूद, हांगकांग का मूल्य इसमें निहित है:

- इसकी सांस्कृतिक संकरता
- इसकी अलग-अलग प्रणालियों को जोड़ने की क्षमता
- उन विचारों के प्रति इसका खुलापन जो राजनयिक चैनलों के माध्यम से औपचारिक रूप से आगे नहीं बढ़ सकते हैं

यह वैश्विक स्थिति के लिए एक रूपक के रूप में खड़ा है - प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच फंसे देश, उन मार्गों की तलाश करते हैं जो भू-राजनीति अक्सर अस्पष्ट करती हैं।

लोगों से लोगों के बीच संबंध, भले ही मामूली हों, आशा का स्रोत बने रहते हैं, जब आधिकारिक चैनल लड़खड़ा जाते हैं तो स्थिरता को सहारा देते हैं।

6. भारत के लिए सबक

अमेरिका-चीन समीकरण वैश्विक जलवायु को आकार देता है, लेकिन भारत को यह चुनना होगा कि तूफान से कैसे निपटना है।

a) रणनीतिक स्वायत्तता को संरक्षित करें

भारत को न तो अमेरिकी बयानबाजी को प्रतिध्वनित करना चाहिए और न ही चीनी आख्यानों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार करना चाहिए। इसके बजाय, इसे मजबूत करना चाहिए:

- घरेलू तकनीकी क्षमता
- आर्थिक लचीलापन
- संस्थागत ताकत

बी) कठोर बायनेरिज़ से बचें

दुनिया द्विध्रुवीय नहीं है; यह खंडित और तरल है। भारत को लचीला रहना चाहिए।

c) भू-राजनीति से परे जुड़ाव

युवाओं का आदान-प्रदान, सांस्कृतिक कूटनीति और प्रौद्योगिकी के आसपास एक मजबूत सामाजिक अनुबंध उतना ही मायने रखता है जितना कि शिखर सम्मेलन।

घ) व्यापक जोखिमों के लिए तैयार रहें

यदि अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता गहरी होती है, तो वैश्विक शासन कमजोर हो जाएगा - प्रभावित:

- जलवायु वार्ता
- आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता
- महामारी प्रतिक्रिया
- एआई और अंतरिक्ष नियम

भारत को इन प्रणालीगत जोखिमों का अनुमान लगाना चाहिए और तदनुसार बचाव करना चाहिए।

समाप्ति

अमेरिका-चीन संबंध स्थिर जुड़ाव के पहले के पैटर्न पर वापस नहीं आएंगे; अशांति नया सामान्य है। फिर भी प्रबंधित प्रतिद्वंद्विता का विकल्प जीत नहीं है - यह जलवायु आपदाओं से लेकर तकनीकी अराजकता तक, जमिलो, व्यापक जोखिमों की दुनिया है। हांगकांग फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि अगली विश्व व्यवस्था को भव्य रणनीतियों से कम और साझा वैश्विक चुनौतियों पर व्यावहारिक सहयोग से अधिक आकार दिया जाएगा।

भारत के लिए, चुनौती स्पष्ट है: रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना, राष्ट्रीय क्षमताओं में निवेश करना, और वैश्विक कूटनीति में अपने स्वयं के "मध्य स्थानों" पर कब्जा करना। भविष्य के लिए जिम्मेदारी, कल्पना और स्थिर हाथों की आवश्यकता होगी - और सबसे बढ़कर, तेजी से जटिल दुनिया में संवाद के लिए नई शब्दावली बनाने की इच्छा।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आरबीआई मुख्य रूप से दीर्घकालिक रुपये की तरलता लाने के लिए डॉलर/रुपये की खरीद-बिक्री स्वैप नीलामी करता है।

2. 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर से कम है।

3. कच्चे तेल का आयात भारत के कुल आयात का 20% से अधिक है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2
(d) 1, 2 और 3
उत्त:

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: मौद्रिक नीति में बाहरी दबाव के तहत रुपये को स्थिर करने में सीमित जगह है। भारत की प्रबंधित फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट व्यवस्था के संदर्भ में समझाइए। **(150 शब्द)**

Page : 08 : Editorial Analysis

GS. Paper 3 पर्यावरण

UPSC Mains Practice Question : COP30 ने वैश्विक जलवायु वार्ता को "लक्ष्य" से "कार्यान्वयन" में स्थानांतरित करने का प्रयास किया। पेरिस समझौते के संदर्भ में इस बदलाव के महत्व पर चर्चा करें। **(250 शब्द)**

संदर्भ:

ब्राजील के बेलेम में पार्टियों का 30वां सम्मेलन (COP30) एक महत्वपूर्ण क्षण में आया - पेरिस समझौते के एक दशक बाद और एक ऐसे वर्ष में जब वैश्विक तापमान पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया। अमेज़ॅन वर्षावन के प्रतीकवाद द्वारा चिह्नित, COP30 ने वैश्विक जलवायु प्रवचन को बातचीत से कार्यान्वयन में स्थानांतरित करने का प्रयास किया, अनुकूलन, न्यायसंगत परिवर्तन और नवीनीकृत बहुपक्षवाद पर जोर दिया।

पृष्ठभूमि: COP30 क्यों महत्वपूर्ण था

- पेरिस (10-2015) के बाद से 2025 साल - उपलब्धियों और असफलताओं का जायजा लेने का समय।
- 1.5 में 2024 डिग्री सेल्सियस का उल्लंघन - बढ़ती तात्कालिकता का संकेत।
- गहरे भू-राजनीतिक विभाजन बने रहे, विकसित देशों ने जीवाश्म-ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की समयसीमा को आगे बढ़ाया, जबकि विकासशील और पेट्रो-राज्यों ने वित्त और लचीलेपन की मांग की।
- अमेरिका की अनुपस्थिति ने विकसित देशों के सौदेबाजी गठबंधन को कमजोर कर दिया।

COP30 में प्रमुख परिणाम और विषयगत बदलाव

1. लक्ष्य से कार्यान्वयन की ओर बदलाव

ब्राजील के राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि वैश्विक जलवायु राजनीति को उच्च-स्तरीय प्रतिबद्धताओं से आगे बढ़ना चाहिए। मुतिराओ" - सामूहिक लामबंदी का एक ब्राजीलियाई विचार - बहुपक्षवाद में विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए उजागर किया गया था।

इस बदलाव का मतलब था:

- वित्त के संचालन पर अधिक जोर (अनुकूलन, संक्रमण और लचीलापन के लिए)।

Fighting the fire

COP30 sought to change the narrative by focusing on 'implementation'

The 30th edition of the Conference of Parties (COP) concluded in Belem, Brazil, a city chosen for its proximity to the Amazon rainforest. The symbolism was high this year. It is 10 years since the Paris Agreement was signed by 195 countries – a pact to ensure that the globe did not heat up beyond 2°C of pre-industrial times and, as far as possible, contain it to 1.5°C. That was a goal easier stated than done; 2024 ended up being the first time that temperatures breached the 1.5°C territory though it will require several more such transgressions for 1.5°C to be the 'new normal'. In all the years since, COPs have been about systematically getting all countries to move on the path of restructuring their economies away from their fossil-fuel hardwiring; apportioning responsibility – and finance – in ways to actualise these goals, and finally work towards addressing the damage that climate change had already done to societies, livelihoods and ecologies. While there has been success, in that most countries – even the United States – recognise that renewables are the future of energy, it has been challenging for countries to execute the transformation while also growing their economies and keeping their competitive edges sharp. This has led to the formation of the two broad blocs – one led by developed countries and affiliated allies that has pushed for hard targets and road maps to phase out fossil fuels, and the other by developing countries or petro states who reject such prescription and demand more money and action from the developed countries.

The Brazil COP sought to bring a change in the narrative by stressing 'implementation', and reminding the world that multilateralism and 'mutirão' (coming together) were indispensable to the Paris Agreement. While the absence of the U.S. weakened the developed country blocs, this year saw greater thrust on topics such as 'adaptation' and 'just transition' – concepts that acknowledge the everyday effects of climate change and stress practical preparatory steps and finance pledges to help countries burnish climate defences. India, which has been one of the prominent voices for developing country coalitions, was welcoming of the Brazil Presidency's acknowledgement of concerns but did not declare its updated Nationally Determined Contributions (actions on adopting clean energy). The COP's negotiation process often leaves one wondering about the net gains made, given that pollution, deforestation and climate denialism seem more voluble and visible but, as it is often said, this is humanity's only opportunity to mitigate a cataclysm of its making.

- केवल दीर्घकालिक इरादों की घोषणा करने के बजाय राष्ट्रीय जलवायु कार्यों को ट्रैक पर लाने के लिए अधिक धक्का।

2. अनुकूलन पर बढ़ा हुआ ध्यान

ऐतिहासिक रूप से, जलवायु वार्ता शमन-भारी रही है। COP30 ने जलवायु अनुकूलन की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वीकार किया:

- जलवायु परिवर्तन पहले से ही जीवन, आजीविका, कृषि, जल चक्र और पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर रहा है।
- देशों को जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे, पूर्व-चेतावनी प्रणाली, तटीय सुरक्षा आदि के लिए समर्थन की आवश्यकता है।
- विकासशील देशों ने अनुकूलन वित्त को बढ़ाने की मांग की, क्योंकि मौजूदा प्रवाह जरूरतों से बहुत कम है।

3. जस्ट ट्रांजिशन ने केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया

"जस्ट ट्रांज़िशन" यह पहचानता है कि:

- जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की सामाजिक और आर्थिक लागत होती है, खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए।
- कोयला, तेल और गैस पर निर्भर श्रमिकों, समुदायों और उद्योगों को नियोजित पुनर्वास की आवश्यकता है।
- COP30 चर्चाओं में स्वीकार किया गया कि जलवायु जिम्मेदारी को विकासात्मक अनिवार्यताओं के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।

इसने वैश्विक जलवायु राजनीति में निष्पक्षता को फिर से पेश किया।

4. जीवाश्म-ईंधन फेज-आउट पर निरंतर विभाजन

दो व्यापक ब्लॉक बने रहे:

(A) विकसित राष्ट्र

- जीवाश्म-ईंधन चरण-आउट के लिए तेज, सत्यापन योग्य समयसीमा की वकालत की।
- फिर भी विश्वसनीयता की कमी थी क्योंकि:
    - कई लोग अभी भी प्राकृतिक गैस की खोज में भारी निवेश करते हैं।
    - जलवायु वित्त प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हुई हैं।

(B) विकासशील देश और पेट्रो-राज्य

- तर्क दिया कि जबरन चरण-आउट आर्थिक सुरक्षा को खतरा है।
- पर जोर दिया:
    - उच्च अनुदान और कम लागत वाला वित्त।
    - विभेदित जिम्मेदारियों की पहचान।

COP30 ने एक कठिन वैश्विक "जीवाश्म चरण-आउट" समयरेखा का उत्पादन नहीं किया, जिससे लगातार गलती रेखाओं का पता चला।

□□□□□ □□□□□□

COP30 में भारत की स्थिति

1. ब्राज़ील की कथा का समर्थन

भारत ने कार्यान्वयन-प्रथम एजेंडे का स्वागत किया, जो इस पर अपनी दीर्घकालिक स्थिति के अनुरूप है:

- जलवायु न्याय
- इक्विटी और सीबीडीआर (सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां)
- पूर्वानुमानित वित्त की मांग

2. कोई अद्यतन एनडीसी घोषणा नहीं

भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अपने अगले दौर की घोषणा नहीं की। कारणों में शामिल हैं:

- भविष्य के जलवायु वित्त पर स्पष्टता का अभाव।
- घरेलू औद्योगिक परिवर्तन अभी भी विकसित हो रहा है।
- एक मजबूत आर्थिक स्थिति से बातचीत करने की इच्छा।

3. विकासशील देशों के गठबंधनों के लिए मजबूत आवाज

भारत ने दोहराया:

- कि विकासशील देश विकास से समझौता नहीं कर सकते।
- वैश्विक शमन प्रयासों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता समर्थन और जलवायु वित्त पोषण होना चाहिए।

COP30 में व्यापक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया

1. जलवायु वित्त घाटा

- $100 बिलियन/वर्ष का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है।
- अनुकूलन वित्त कुल जलवायु वित्त का 25% <।
- हानि और क्षति कोष गंभीर रूप से कम पूंजीकृत बना हुआ है।

2. कमजोर बहुपक्षवाद

- अमेरिका की अनुपस्थिति पहले के सीओपी के दौरान देखे गए शून्य से मिलती-जुलती थी।
- बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव जलवायु सहयोग को प्रतिस्पर्धा में बदलने का जोखिम उठाते हैं।

3. जमीनी हकीकत बिगड़ती जा रही है

- विश्व स्तर पर प्रदूषण और वनों की कटाई बनी हुई है।
- चरम मौसम की घटनाएं अधिक बार होती हैं।
- कई देशों में जलवायु इनकारवाद और राजनीतिक पुशबैक फिर से उभर कर सामने आ रहे हैं।

आगे की चुनौतियाँ

- महत्वाकांक्षा-कार्यान्वयन अंतर को बंद करना: राष्ट्र अधिक वादा करते हैं लेकिन कम करते हैं।
- निष्पक्षता सुनिश्चित करना: विकसित देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन बोझ को अपर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है।
- कम कार्बन संक्रमण का वित्तपोषण: ग्लोबल साउथ को खरबों की आवश्यकता है, अरबों की नहीं।
- आर्थिक झटके के बिना संक्रमण: विशेष रूप से कोयला- और तेल पर निर्भर क्षेत्रों के लिए।

आगे की राह

- पारदर्शी, सत्यापन योग्य प्रवाह के माध्यम से जलवायु वित्त में विश्वास का पुनर्निर्माण।
- प्रौद्योगिकी साझाकरण (हरित हाइड्रोजन, बैटरी, कार्बन कैप्चर) के आसपास उत्तर-दक्षिण सहयोग को गहरा करना।
- राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर अनुकूलन रणनीतियों को मजबूत करना।
- प्रतिज्ञाओं और समयसीमा की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सीओपी प्रक्रिया में सुधार।
- स्वदेशी और वन समुदायों को सशक्त बनाना - विशेष रूप से अमेज़न देशों में प्रासंगिक।

समाप्ति

ब्राज़ील में COP30 ने वैश्विक जलवायु राजनीति में एक आवश्यक बदलाव का संकेत दिया: आकांक्षात्मक प्रतिबद्धताओं से लेकर कठोर कार्यान्वयन तक। जबकि विभाजन बना हुआ है और जलवायु चुनौतियां तेज हो रही हैं, अनुकूलन, न्यायसंगत परिवर्तन और बहुपक्षीय सहयोग पर नए सिरे से जोर आगे बढ़ने का एक यथार्थवादी मार्ग प्रदान करता है। 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पहले ही टूट चुकी है, यह दशक अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक उथल-पुथल को रोकने के लिए मानवता की संकीर्ण खिड़की का प्रतिनिधित्व करता है - निरंतर, सामूहिक और न्यायसंगत कार्रवाई को पहले से कहीं अधिक जरूरी बना देता है।